संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

मैं संविधान में एक बहुत छोटा संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं । यद्यपि यह संशोधन छोटा है तथापि इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है कि वह इसी प्रकार के अन्य संशोधनों का अग्रदूत है ।

यह संशोधन दादरा और नगर हवेली के भारत में एकीकरण से संबंध रखता है । यह शब्द 'नगर' है न कि 'नागर' जैसा कि कई अधिकांश लोग कहते हैं ।

इस समावृत्त बस्ती का इतिहास सभी सदस्यों को ज्ञात है । कुछ वर्ष पूर्व नगर हवेली और दादरा के कुछ साहसी व्यक्तियों ने पुर्तगाली सैनिकों, पुलिस और वहां के अधिकारियों को मार भगाया और एक स्वतंत्र प्रदेश की स्थापना की । हमारी उनसे पूरी सहानुभूति है और वे भी हमसे सहानुभूति रखते हैं ।

वस्तुतः जैसा कि हेग न्यायालय में सिद्ध किया गया यह कार्य वहां के निवासियों का था न कि भारत सरकार का । स्वतंत्रत प्रदेश की स्थापना होने पर हमने पुर्तगालियों को भारत के राज्य क्षेत्र से होकर आने तथा दादरा और नगर हवेली के निवासियों का दमन करने की अनुमति नहीं दी । अतः वे अपनी स्वतंत्रता कायम रख सके ।

पुर्तगाल की सरकार यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में ले गई तथा इन राज्य क्षेत्रों से होकर मार्ग का दावा किया । यह मामला कई वर्ष चलता रहा और वस्तुतः इसी कारण हम इन राज्य क्षेत्रों तथा गोआ के संबंध में भी वह कदम नहीं उठा सके जो हम उठाना चाहते थे । अन्ततोगत्वा इस मामले का निर्णय कर लिया गया यद्यपि यह निर्णय शतप्रतिशत उस प्रकार का नहीं हुआ जैसा कि हम चाहते थे तथापि इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि हमने जो बुनियादी रवैय्या अपनाया था वह बिल्कुल ठीक था, इससे यह प्रकट होता हैं कि हम इन राज्य क्षेत्रों को भारत संघ में शामिल कर सकते हैं जैसा कि दादरा और नगर हवेली के निवासियों ने कई बार अपनी इच्छा को व्यक्त भी किया है । वहां की वरिष्ठ पंचायत ने इस आशय का संकल्प भी पारित किया है ।

हेग न्यायालय के निर्णय के पश्चात् हमने इस मामले पर अग्रेतर विचार किया और इस निश्चय पर पहुंचे कि हमें वहां के पंचायत की प्रार्थना स्वीकार करनी चाहिये । इसके परिणामस्वरूप हमने यह विधेयक संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है । इसके साथ एक संबन्धित विधेयक भी रखा गया है जो कि दादरा और नगर हवेली का इस सभा में प्रतिनिधित्व से सम्बन्ध रखता है ।

हमने उन्हें संघ राज्य क्षेत्र में इस कारण रखा है कि हम उनका विभाजन कर उन्हें गुजरात या महाराष्ट्र में शामिल नहीं करना चाहते हैं । हम वहां के निवासियों की इच्छा को क्रियान्वित कर रहे हैं । उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक एकक समझा जाये । मैं नहीं जानता कि सुदूर भविष्य में क्या होगा तथापि निकट भविष्य में वे संघीय राज्य क्षेत्र बने रहेंगे । अतः किसी माननीय सदस्य द्वारा यह कहना कि उनके टुकड़े किये जायें वहां के निवासियों के इच्छाओं की विरुद्ध कार्य करना होगा ।

कुछ संशोधनों में यह सुझाव रखा गया है कि हमें इसमें गोआ, दमन और दीव के नाम भी इसमें जोड़ने चाहिये थे । इन संशोधनों से माननीय सदस्यों की इच्छाओं का पता चलता है तथापि वे सत्य के विपरीत हैं । हमारा सम्बंध दादरा और नगर हवेली में हुई घटनाओं से हैं । यहां की अवस्था

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

गोआ, दमन और दीव से भिन्न है क्योंकि गोआ, दमन और दीव अभी भी पुर्तगाल को हमने यह कहा है कि ११ अगस्त से यह प्रदेश भारत संघ का एक अंग बन जायेगा। निसन्देह हमारी इच्छा है कि गोआ भारत संघ का एक भाग बने। तथापि जैसा कि मैंने कहा है कि दादरा और नागर हवेली का भारत में शामिल होना भविष्य के लिये एक अच्छा संकेत है।

इस सम्बन्ध में यह जानना उपयोगी होगा कि पुर्तगाली साम्राज्य आज के औपनिवेशवाद और साम्राज्य की समाप्ति वाले दिनों में सबसे बड़ा साम्राज्य है। यह विचित्र बात है कि जब इससे बड़े बड़े साम्राज्य विलीन हो रहे हैं तो यह साम्राज्य अभी भी जारी है। निसन्देह अफ्रीका के अंगोला प्रदेश में इसकी स्थिति बहुत दर्दनाक और खतरनाक है, कदाचित साम्राज्यवाद के पुराने इतिहास में भी वहां होने वाले दमन का मुकाबला नहीं मिलेगा। तथापि मुझे इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है कि अंगोला और मोजाम्बिक इत्यादि में पुर्तगाल साम्राज्य का विनाश निश्चित है।

दुख का विषय यह है कि हमें अंगोला के विषय में सही तथ्य ज्ञात नहीं होते हैं, क्योंकि वहां किसी को नहीं जाने दिया जाता है। कुछ समय पूर्व कुछ अंग्रेज मेथोडिस्ट मिशनरी वहां से आये और उन्होंने वहां होने वाले उत्पीड़न के सम्बन्ध में दर्दनाक हाल बताये। सबसे पहिली बार इस प्रकार विश्वसनीय सूत्रों से समाचार मिल सके। यद्यपि अभी तक बहुत कम हालात ज्ञात हुए है तथापि जिन हालातों का पता लगा है उनसे यह ज्ञात होता है कि वहां के पुर्तगाली अधिकारी और वस्तुतः पुर्तगाली सरकार भर्त्सना के योग्य हैं। मेरे विचार से पुर्तगाली सरकार वहां अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर सकती हैं। हम अंगोला के निवासियों से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं।

गोआ के बारे में मुझे अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर मैं कहूं कि गोवा की आजादी अफ्रीका में होने वाली घटनाओं पर निर्भर है—तो बात बड़ी अटपटी, बड़ी बेतुकी लगेगी। यह कहना गलत भी होगा और हमारे लिये यह फख्र की बात भी नहीं होगी कि गोवा की आजादी और भारत में उसको मिलाने के लिये हम दूसरे देशों में होने वाली घटनाओं का मुंह ताकें। लेकिन असल में यह सवाल निर्भर करने का नहीं है। इन मामलों में हमें पूरी तसवीर को देखना पड़ता है, उन सभी चीजों को देखना पड़ता है जो एक दूसरे पर असर डालती हैं। वैसे गोवा में वही होगा जो भारत की जनता और सरकार करेगी। और ये, दोनों ताकतें ठीक वक्त पर पहल करेगी।

इसलिये यह एक बड़ा आसान सा, सीधा-सादा विधेयक है। मुझे यकीन है कि सभा का हर सदस्य इसे स्वीकार कर लेगा। हम अपने मन से तो नये स्थान इसमें जोड़ नहीं सकते। वह न तो असलियत से मेल खायेगा और न सही ही होगा। हम अपने मंशे का इजहार किसी दूसरे तरीके से कर सकते हैं। इस विधेयक में तो उसे शामिल नहीं कर सकते। ऐसे चलते-फिरते ढंग से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता।

इसीलिये हमें इसे इसी रूप में स्वीकार करना चाहिये। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के एक भाग को संवैधानिक रूप में भारत में मिलाने का यह पहला मौका है। और, यह एक तरह से आगे आने वाले वक्त का, भविष्य का लक्षण है।

दादरा और नगर हवेली की वरिष्ठ पंचायत के सदस्य यहां दिल्ली में इस ऐतिहासिक अवसर पर आये थे।

मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में एक स्वतन्त्र राज्य क्षेत्र की भांति कितने अच्छे ढंग से प्रशासन चलाया है। हमारा प्रशासक उनको जब तब राय देता रहता है। शिक्षा और अन्य कई क्षेत्रों में काफी काम हुआ है। उन्होंने १८ लाख रुपये अतिरिक्त राशि जमा कर ली है।

†**एक माननीय सदस्य :** तीस लाख ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** काफी बड़ी राशि है । यह भारत की संचित निधि में जमा की जायेगी । इन राज्य-क्षेत्रों के सुधार पर और भी ज्यादा बड़ी राशियां खर्च की जायेंगी ।

मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): हमें दादरा और नगर हवेली की जनता को उनकी अपनी गुलामी के बन्धन काटने के लिये बधाई देनी चाहिये ।

उन्होंने काफी बड़ा बलिदान किया है और देशभक्ति की एक मिसाल हमारे सामने रखी है । प्रधान मन्त्री को इस बात पर जोर देना चाहिये था कि ये लोग भारत की जनता के ही अंग हैं, शताब्दियों से रहे हैं । भारत में शामिल होना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है ।

डियू, डामन और गोवा की जनता भी हमारी जनता का ही एक अंग है । दुर्भाग्य यही है कि वे अभी तक अपने को स्वतन्त्र नहीं कर पाये हैं । समय आयेगा जब हम उनको भी शेष भारत की भांति अहिंसापूर्ण संघर्ष के द्वारा मुक्ति दिलायेंगे ।

विदेशियों से अपना प्रदेश वापस लेना, मुक्त कराना हमारा अधिकार है । बुनियादी तौर पर वे भारत के ही अंग हैं ।

अभी चूंकि अहिंसक नीति हमें सदा ही सफलता दिलाती रही है, इसलिये हमें हिंसापूर्ण संघर्ष की आवश्यकता महसूस नहीं हुई । इसका यह मतलब नहीं कि हमें उसका अधिकार ही नहीं रहा ।

भारत का प्रत्येक नागरिक इस विधेयक का समर्थन करेगा ।

†**श्री डांगे** (बम्बई नगर—मध्य) : प्रधान मन्त्री के भाषण में कुछ खामियां रह गई हैं । विधेयक छोटा सा है, पर इसका अर्थ काफी बड़ा है । पुर्तगाली साम्राज्यवाद का पंजा ढीला होना—एक बहुत बड़ी बात है । हमें दादरा और नागर हवेली की जनता को बधाई देने में सात वर्ष लग गये । वे विद्रोह करते रहे और हम अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का इन्तजार करते रहे । क्या गोवा के लिये भी हम इसी तरह इन्तजार करेंगे ? जब वे अपने को दासता से मुक्त कर लेंगे तब हम उनसे कहेंगे कि अब हम में मिल सकते हो !

दादरा और नगर हवेली की मुक्ति का रहस्य यह है कि बीच में भारतीय क्षेत्र पड़ने के कारण पुर्तगाली फौजें इन क्षेत्रों में नहीं आ सकती थीं ।

आज से सात साल पहले हमारे लोगों ने १५ अगस्त को बांदरा की सीमा से गोवा की ओर प्रयाण किया था । उन पर गोलियां बरसाई गई थीं । लेकिन हमारी भारत सरकार ने उन ५००० स्वयंसेवकों की क्या सहायता की ? हम अंगोला के विद्रोहियों के कत्ल पर आंसू बहाते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिये पुर्तगाली साम्राज्यवाद के विरुद्ध दूसरा मोर्चा क्यों नहीं खोलते ? दुनिया के बहुत से छोटे-छोटे बौने देशों ने अपनी दासता की बेड़ियां काट ली है, पर हम ४० करोड़ अपने गोवा को मुक्त नहीं करा सके । यह एक काफी बड़ी चीज़ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में